eral Licence (OGL) of items which are in short supply like edible oils and pulses are being permitted in order to augment the total availability of these items. Government has decided to import 1.5 million tonnes of wheat through State Trading Corporation to augment its availability. Some of the essential commodities like rice, wheat, sugar imported palmolein and kerosene are also being supplied through the Public Distribution System and Cooperative Stores at below market prices. Stringent actions are being taken against hoarders and black marketeers and others indulging in unfair trade practices under the Essential Commodities Act and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act etc. by the State/UT Governments.

Statement

Percentage variation in WPI of essential commodities as on 13.6.98 over different periods

Percentage variation (as on 13.6.98)

Commodity	Over 1 month 13.6.98/16.5.98	over 3 months 13.6.98/14.3.98
Pulses (Sub-group)	-3.6	-5.5
Gram	-8.8	-24.8
Arhar	-2.4	10.7
Moong	0.5	-1.6
Masur	-2.2	5.9
Urad	-1.0	2.4
Edible oils (Sub-group)	3.3	-6.1
Vanaspati	Steady	0.3
Groundnut oil	6.3	11.1
Mustard oil	6.7	18.0
Coconut oil	0.3	-7.3
Rice	1.4	2.9
Wheat	0.9	-3.1
Vegetables (Sub-group)	2.7	64.0
Potatoes	4.1	126.7
Onions	1.8	-14.4
Sugar	Steady	0.9
Salt	Steady	0.7
Tea	-5.9	-1.6

Impact of fall in Sugar Production

2011. SHRI RAJNATH SINGH SURYA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to decrease in sugar production this year and also due to increase in per-capita allowance of sugar through PDS, pressure on sguar sellers has increased;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have prepared a plan of action to make up this shortage; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) to (d) The production of sugar during the current sugar season 1997-98 is marginally less as compared to the last sugar season. There has been no change in per capita allocation of sugar under Public Distribution System. The releases of free sale sugar in the open market have been higher during the current season in comparision to the last season 1996-97. With the Carry over stocks of the last season and the estimated production of sugar during the current sugar season 1997-98, the Central Government would be able to meet the domestic consumption requirement of sugar in the country.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन

2812. श्री राम गोपाल यादव: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है अथवा विचार करेगी,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता मंचों को सरकार किस तरह प्रभावकारी बनाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक

प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उसमें उपयुक्त संशोधनों के संबंध में सुझाव देने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर एक कार्य दल तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय के निर्देश पर एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। दोनों दलों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद टिप्पण का एक मसौदा तैयार किया गया है और उसको विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचार जानने के लिए उन्हें भेजा गया है।

सोया तेल कारखाने

2013 **श्री राघवजी:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य वार सोया तेल के कितने कारखाने हैं;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान उक्त कारखानों द्वारा अपनी कुल क्षमता में से कितनी औसत क्षमता प्राप्त की गई; और

(ग) क्या सोयाबीन आयात करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उपरोक्त कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें; यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) वर्ष 1997-98 में सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्सारण संयंत्रों की संख्या 171 हैं आगे विवरण में राज्यवार स्थिति दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्सारण संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता
1995-96	26.2
1996-97	25.7
1997-98	28.0 (अनन्तिम)

(ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि सोयाबीन का विधायन और इससे तैयार होने वाली खाद्य सामग्री (मील) का निर्यात करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को एक मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की अनुमति दी जाए।

विवरण

1997-98 के दौरान सोयाबीन का विधायन करने वाले विलायक निस्सारण संयंत्रें की संख्या

जोन/राज्य	यूनिटों की संख्या
उत्तर प्रदेश	6
पंजाब	2
राजस्थान	19
हरियाणा	2
उड़ीसा	-
पश्चिम बंगाल	1
गुजरात	19
मध्य प्रदेश	68
महाराष्ट्र	35
आन्ध्र प्रदेश	12
कर्नाटक	5
तमिलनाडु	2

Reviewing Minimum Purity Standard for Pickles in Oil

2014. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether minimum purity standards for "Pickles in Oil" prescribed by rules under Prevention of Food Adulteration Act, 1955 have created certain troubles in the production of the same, because people in Kerala find this standard not suitable to their tastes and food habits;

(b) whether the Central Committee for food standards has refused to review the existing standards and Government of Kerala has requested for a further review; and

(c) whether Government will direct the Committee for a review of its earlier decision of allow the State Government to formulate their own rules under the PFA Act?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) The standards for "Pickles in Oil" laid down under P.F.A. Rules, 1955 are the minimum statutory standards applicable